

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1843  
बुधवार, 04 अगस्त, 2021/13 श्रावण, 1943 (शक)

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण नौकरी गंवाने पर मुआवजा दिया जाना

1843. श्री के.टी.एस. तुलसी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार ने अंतराल के दौरान भूकम्प, बाढ़ इत्यादि जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दिये जाने वाले मुआवजे की तर्ज पर कोविड-19 महामारी के कारण नौकरी गंवाने वाले व्यक्तियों को रोजगार और आर्थिक मुआवजा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और
- (ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन को बढ़ावा देने एवं आजीविका की सुरक्षा हेतु अनेकों पहलें की हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आत्मनिर्भर भारत पैकेज का आरंभ किया गया था।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों, जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है।

पीएम स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था, ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों में से 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार ने एमजीएनआरईजीए मजदूरी को 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% कर दिया गया है, जो कि 90 दिनों तक देय है। इसके साथ-साथ उन बीमित कामगारों, जिन्होंने महामारी के कारण रोजगार गंवा दिया है, के लिए लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तों में छूट है।

\*\*\*\*\*